व्यवसायिक जगत ने बजट का मोटामोटी स्वागत किया

कोलकाता, 16 मार्च। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आज वर्ष 2012-13 का बजट संसद में पेश किया। बजट पर चेम्बरों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकतर व्यवसायिक संगठनों ने बजट का स्वागत किया है।

कलकत्ता चेम्बर ने बजट प्रस्तावों का स्वागत किया है। चेम्बर की अध्यक्षा श्रीमती अलका बांगड़ ने कहा कि कृषि, मूलभूत ढांचे, आवास, खुदरा एवं ऊर्जा क्षेत्रों में बजट में धन प्रावधान सीमा शुल्क में कमी एवं अन्य राहत से बढ़ावा दिये जाने की कोशिश की है। कृषि में प्रचुर व्यय से राजस्व पैदा करने एवं रोजगार की संभावना बढ़ाने का प्रशंसनीय कदम उठाया गया है। लेकिन लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिये विशेष पैकेज व प्रोत्साहन की पहल नहीं किया जाना दुर्भाग्यजनक है।

गुजरात एनआरई कोक लि. के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार जगतरामका ने बजट पर निराशा व्यक्त की है। उनके अनुसार यह मात्र लेखा जोखा है एवं विकासोन्मुख बनाने की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

भारत चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक ऐकत ने बजट को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। श्री ऐकत ने विज्ञप्ति में कहा है कि राजीव गांधी इक्विटी योजना का प्रस्ताव किया है, इसमें निवेश करने वालों को जहां सुरक्षा की गारंटी रहेगी, वहीं अधिक ब्याज मिलेगा। सर्विस टैक्स एवं एक्साइज ड्यूटी में बढ़ातरा का प्रस्ताव किया है, लेकिन इसका आमलोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

मर्चेंट्स चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक जालान ने बजट को सक्रिय बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बजट से लघु उद्योग एवं टेक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट में निवेश का माहौल बनाने का प्रयास किया है। श्री जालान ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा एक्ट के प्रावधान से आमलोगों को काफी लाभ मिलेगा।

आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप के चेयरमैन संजीव गोयनका ने बजट को आर्थिक विकास को बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने पावर सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ टैक्स फ्री बांड, थर्मल पावर कंपनियों से 2 वर्ष के लिए टैक्स में छूट, सनसेट क्लाज का विस्तार, कोयला खदानों से प्राप्त कोयले से प्राप्त कस्टम ड्यूटी में छूट, प्लांट लोड फेक्टर में बदलाव से ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

बंगाल नेशनल चेम्बर के अध्यक्ष तेजमय राय चौधर ने कहा है कि कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला बजट है तथा 15 हजार करोड़ के निवेश के लिए केपिटल फंड बनाने की योजना स्वागत योग्य है। इसी के साथ लघु उद्योगों के लिए मशीन एवं अन्य सामानों के टैक्स में छूट जैसे प्रावधान स्वागत योग्य है।

इस्टर्न इंडिया करूगेटेड बॉक्स मेनुफेक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत केडिया ने कस्टम इनपोट ड्यूटी में कटौती की अपील की है। श्री केडिया ने कहा है कि क्राफ्ट पेपर कच्चे माल से बनाये जाते हैं, जिसमें छूट देना जरूरी है। खाद्य प्रसंस्करण, फल, सब्जी, खाद्य तेल, आटा, चाय, बिस्कुट, डायरी उत्पाद, रक्षा, होर्टिकल्चर आदि की पैकिंग कागजों से की जाती है।

फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ कार्टेज एंड स्माल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुखेन्दु विकास घोष ने कहा है कि लघु उद्योग को बढ़ाने क वित्त मंत्री ने पहल की है। लेकिन इसमें और छूट की जरूरत है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में भी राहत की जरूरत है ताकि उद्योगपति निवेश कर सके।

इाडयन चम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री वर्द्धन गोयनका ने बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे उद्योग को जहां बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नेशनल मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग, टैक्स फ्री, इन्फ्रा बांड जैसे कदम स्वागत योग्य है।